अमल जरूरी

कचरा फायदे का सौदा

किया जाए? यह शासन-प्रशासन के ठाने के लिए कर्मचारियों के अभाव में उठाने में विफल रहते हैं। इसका एक निकाय कचरे के बदले लोगों को कुछ हां फेंकने के बजाय घर में ही रखेंगे। , कागज, कांच आदि को पुनर्चक्रित

आकाश पाण्डेय
सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल

कार

जागरूकता और पर्यावरण नीतियों है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा है। इससे सबसे अधिक नुकसान वालों को होता है क्योंकि वे बीमारी कार को त्वरित कार्यवाही करते हुए कानून बनाना चाहिए और इसके चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति और ने की जरूरत है। समय रहते हुए ही संकट में आएगी।

स्वाति
जमशेदपुर, झारखण्ड

अलग हो प्रबंधन

तभी होगा, जब हम स्वच्छता के जीवन में उसे शामिल करेंगे और को घर पर ही गीला और सूखा ानीय निकाय के साथ साथ सफ जाए। उसके लिए कर्मचारी की और व्हाट्सऐप के जरिये उसकी के उचित निस्तारण की व्यवस्था कर कचरे की खाद बनाई जाए, यदा भी होगा और रोजगार भी फायदे का संसाधन माना जाए। वस्तुएं फेंकने से रोकने के लिए र नागरिक, जवाबदेह प्रशासन समाधान हो सकता है।

नीतीश कुमार
बेगूसराय, बिहार

गा समाधान

न केवल स्वच्छ भारत अभियान ईमानदारी से कोशिश भी की। जितना करना था, उसने कर ा फेंकने में समझदारी दिखाए। लका द्वारा बताई और निर्धारित नागरिकों को इस बात का भी र के कचरे के लिए तय किए ाल करें। कचरा फेंकते समय अभियान की दिशा में बड़ी

बकौल विश्लेषक

सूखे व गीले कचरे का अलग-अलग हो प्रबंधन

केंद्र सरकार ने कचरे की समस्या के समाधान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित तो कर दिया, लेकिन इन नियमों के मुताबिक स्थानीय निकाय काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या कचरे को गीले व सूखे कचरे के रूप में विभाजित नहीं कर पाना है। गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने से सूखा कचरा मसलन प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, धातु का पुनर्चक्रीकरण किया जा सकता है। गीले कचरे को कंपोस्ट किया जा सकता है। कंपोस्टिंग बड़े शहरों में करने पर गीले कचरे के लिए खरीदार मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसकी परिवहन लागत काफी है। इसलिए गीले कचरे के मामले में बायो मेथेनेशन प्लांट लगाना चाहिए। इस तरह के प्लांट दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक जगह लगाना पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन शहरों में ये प्लांट 10-12 जगहों पर लगाए जाने चाहिए। गीले कचरे के इस प्लांट में मीथेन गैस निकलेगी। इसे उद्योगों को आपूर्ति कर सकते हैं। इस संयंत्र से कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है। हालांकि कंपोस्ट बनाना आसान नहीं है। इसके लिए पैसा व तकनीक भी चाहिए। इसलिए सरकार को कंपोस्ट बनाने में रुचि रखने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए। कचरे की समस्या के समाधान के लिए सरकार को पीपीपी मॉडल पर कचरे से ऊर्जा उत्पादन का काम शुरू करना चाहिए। इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हो और इसका संचालन सरकार करे। सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की व्यवस्था करनी होगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन पर स्थानीय निकायों पर जुर्माना लगना चाहिए। सरकार को कचरा प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरुक व शिक्षित करने की आवश्यकता है। अब देश में और कचरा डंपिंग साइट नहीं होनी चाहिए। ऐसा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का अनुपालन करने से ही संभव है। सूखे व गीले कचरे के प्रबंधन की बहुत सी तकनीकें उपलब्ध हैं। अगर सरकार कचरे की समस्या का स्थायी समाधान चाहती है तो उसे जबावदेही और उत्तरदायित्व के साथ सूखे व गीले कचरे का प्रबंधन करना होगा।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

डॉ. अमिय कुमार साहू
अध्यक्ष, नैशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया

आधुनिक तकनीक और जन-सहभागिता से खत्म होगी समस्या

कूड़े के पहाड़ कचरा निष्पादन के प्रति हमारी वर्षों से चली आ रही अनदेखी का नतीजा हैं। रोज निकलने वाले कचरे के लिए अब लैंडफिल साइट नहीं है। जो हैं वो भर चुकी हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तकनीक, कानून व प्रशासन के साथ जन-सहभागिता जरूरी है। वर्ष 2000 के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट ऐंड हैंडलिंग) रूल्स में कचरे को अलग अलग करके बचे हुए कचरे के लिए निश्चित स्थान जमा करने को कहा गया। गीले और सूखे कूड़े को अलग करके इकट्ठा करने की कोशिश में ... नहीं मिली है। इसके लिए

फॉर्मूला वन को लाखों ... करने का फरमान

दुनिया भर ... का आयोज... कंपनी ... चैंपियनशि... में हुई ए... 154.5 ला...
उच्चतम न्यायालय ने निर्देश ... उच्च न्यायालय के पास जमा ... न्यायालय में दायर अपील में ... देनदारी को लेकर सवाल उ... कंपनी ने जेपी स्पोर्ट्स के सह... लेकर 2013 तक फॉर्मूला व... जेपी स्पोर्ट्स के अनुरोध पर ... वन के पक्ष में चार ऋणपत्र ... आरबीएस और लॉयड्स ने ... उच्च न्यायालय ने कहा था इ... जेपी स्पोर्ट्स से मिले भुगता... देनदारी बनती है। आनन-फा... बैंकों से अपनी रकम जारी ... आयकर विभाग ने उसे जब्... ने इस कदम को सही ठह... ने भी इस पर हामी भरी है ... बैंक वाद का निपटारा क... कहा है कि फॉर्मूला वन ने ... करने की कोशिश की है ... जानकारी होने के बावजू... के जरिये भुनाने की कोशि...

पुराने अनुबंध के ... का चयन सही

उच्चतम न्यायालय ने ... कहा है कि अगर मध्य... में 2015 में किए गए ...

Our Company was ...
Companies, Gujara...
please refer to cha...

PROM...

INITIAL PUBLIC ...
RS.10/- EACH F...
PREMIUM OF R...
"ISSUE"), OF W...
RS.[•]/- PER E...
MARKET MAK...
MAKER RESER...
FOR CASH AT ...
REFERRED TO ...
RESPECTIVEL...
FACE VALUE O...
* Number of sh...
** Subject to ...
THE ISSUE IS ...